

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1586 का उत्तर

आठ नई रेलवे परियोजनाओं की स्थिति

1586. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अगस्त, 2024 में आठ नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है;
- (ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और इनकी लंबाई कितनी है और ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थित हैं;
- (ग) ऐसी नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित बजट और समय-सीमा क्या है;
- (घ) वर्ष 2023-24 में 5200 किलोमीटर रेल मार्ग को जोड़ने में सरकार की उपलब्धि को ध्यान में रखकर रेलवे द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की गति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) मार्च, 2024 तक 62,119 किलोमीटर के बड़ी लाइन के विद्युतीकरण के पूरा होने के बाद शेष नेटवर्क का विद्युतीकरण कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (च) क्या संपूर्ण देश के 6112 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा शुरू कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) सरकार की शेष रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की योजना क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आठ नई रेलवे परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री बाबू सिंह कुशवाहा के अतारांकित प्रश्न सं. 1586 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): जी हाँ। नई रेल लाइन के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अगस्त 2024 में अनुमोदित किया गया है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ करोड़ में)
1	बिक्रमशिला-कटरिया	2,171
2	गुणुपूर-थेरुबाली	1,166
3	भद्राचलम स्टेशन के रास्ते मलकानगिरी-पांडुरंगपुरम	3,592
4	बदामपहाड़-केंदुझरगढ़	1,876
5	जूनागढ़-नबरंगपुर	2,865
6	बुढामरा-चाकुलिया	1,460
7	जालना-जलगांव	5,804
8	बंगरीपोसी-गोरुमहिसानी	2,270

किसी रेल परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा तीव्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के भाग को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशेष स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता (iii) प्राथमिकता परियोजनाओं हेतु निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरीयों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2014-24 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	किया गया विद्युतीकरण (मार्ग किलोमीटर में)
2014 से पहले	21,801
2014-24	44,199

इस समय भारतीय रेल पर कुल बड़ी लाइन नेटवर्क के लगभग 97% मार्ग का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

भारतीय रेल ने हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी व्यवहार्य रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई मुहैया कराने का विनिश्चय किया है। अब तक, 6112 व्यवहार्य रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
